



2026:AHC:17979

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 2568/2026

रामदास

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता :- अनिल कुमार, मोहित सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.पी. सिंह का पक्ष रखते हुए विद्वान अधिवक्ता सुश्री नैना चावला को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का नाम एफ.आई.आर. में अंकित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने सूचनाकर्ता की लगभग 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता के बरामद होने पर उसके बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत बयान दर्ज किए गए, जिनमें उसने प्रार्थी के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. के अनुसार पीड़िता दिनांक 25.07.2025 को रात्रि लगभग 11:00 बजे लापता हुई तथा उसे पुलिस द्वारा दिनांक 26.07.2025 की सायं अकेले बरामद किया गया। पीड़िता के बयानों के अनुसार, जब वह प्रार्थी के साथ आ रही थी, तब उनका एक दुर्घटना (एक्सीडेंट) हुआ, किंतु उसके चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर पर ऐसी कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 29.07.2025 को किया गया, जिसमें उसके आंतरिक परीक्षण में यद्यपि हाइमन फटा हुआ पाया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया तथा निजी अंग में रक्तस्राव पाया गया, किंतु उसके शरीर पर कोई आंतरिक चोट नहीं पाई गई। अतः यह तर्क दिया गया कि यह झूठा फँसाने का मामला है तथा प्रार्थी को दुर्भावना एवं कुटिल मंशा से असत्य एवं निराधार आरोप लगाकर फँसाया गया है। आरोपों की असत्यता को दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तथा वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, प्रार्थी को झूठा फँसाया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया है कि प्रार्थी विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा, न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक होगा उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों का पालन करेगा। आगे यह भी कहा गया है कि प्रार्थी दिनांक 24.09.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण से पूर्व चरण में प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई रियायत प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

4. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

5. अतः, प्रार्थी रामदास को मुकदमा अपराध 258/2025, धारा 64(1), 87 बी.एन.एस., थाना जुनावई, जनपद संभल में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- i) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।
- iv) प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या संदेह के अधीन है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



v) प्रार्थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य उजागर करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ हो।

6. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

27 जनवरी, 2026

मुस्तकीम